जयपुर का तापमान | अधिकतम 23.6°C | न्यूनतम 7.3°C

सूर्यास्त आज शाम 06:00 बजे
सूर्योदय कल सुबह 07:17 बजे
05:45 बजे चन्द्रोदय कल सुबह
06:01 बजे चन्द्रास्त कल शाम
मौसम
अनुमा

दवा माफिया के जाल में सरकार राज्य सरकार की नि:शुल्क दवा योजना का बेड़ा गर्क, काउंटरों से निराश लौट रहे मरीज

व्यवस्था ठप, सारी दवाओं पर अनुपलब्धता का ठप्पा

मजाक कर रही सरकार

एसएमएस अस्पताल में आए बंसीलाल को दवा पर्ची पर डॉक्टर ने दवाइयां लिखी। पर्ची लेकर निशुल्क दवा काउंटर पर गया तो सभी दवाइयों पर अनुपलब्धता का ठप्पा लगा दिया गया। संवाददाता को पर्ची दिखाते हुए मायूस होकर बोला, सरकार तो मजाक कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था।

हमारी भी सुनो

बंसीलाल से बात कर ही रहा था कि एक अन्य मरीज नाथू ने कहा कि मेरी पर्ची देखो, 12 में से 8 नहीं मिली। हद ही हो गई भाईसाहब। हमने वोट इसलिए तो नहीं दिया था कि अच्छी योजनाओं को भी ठप कर दो। आप कुछ करो ... वरना कुछ दिनों बाद तो यहां ताले लगे मिलेंगे।

अब तो पैसे से लेनी होगी

सत्यनारायण ने पर्ची दिखाते हुए कहा कि तीन घंटे तक डॉक्टर को इस आस में दिखाया कि अस्पताल से ही निशुल्क दवा भी मिल जाएगी। पर्ची लिखवाकर काउंटर पर आए तो पता चला कि दवाइयां नहीं हैं। मायूस होकर वे बोले, अब तो पैसे ही खर्च करने होंगे।

फार्मासिस्ट का मन खराब

एसएमएस के एक दवा काउंटर पर फार्मासिस्ट से बात की तो उसने साफ कहा कि योजना का बेड़ा गर्क हो गया है। दवा नहीं मिलती तो मरीज और परिजन उन्हें बुरा-भला कहते हैं। उसने कहा- अस्पताल प्रशासन भी दोषी है, जब स्थानीय निधि का नियम है तो अनुपलब्धता का ठप्पा क्यों?

विकास जैन @ जयपुर
jaipur@patrika.com

देश-विदेश में डंका बजवा चुकी राज्य की नि:शुल्क दवा योजना का 'बेड़ा गर्क' हो गया है। राज्य सरकार दवा माफियाओं के जाल में फंसी हुई है। दवा योजना की लगातार अनदेखी के चलते अस्पतालों के दवा काउंटरों से गायब हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी रोजाना सैकड़ों मरीजों को पर्ची पर लिखी एक भी दवाई काउंटर पर नहीं मिल रही है। 80 फीसदी पर्चियों पर अनुपलब्धता का ठप्पा लगाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका ने एसएमएस सहित विभिन्न अस्पतालों के दवा काउंटरों का जायजा लिया तो दवाओं की उपलब्धता ठप होती नजर आई।

मंडे मेगा स्टोरी

यह नियम भी अब नहीं चलता

सरकार ने यह व्यवस्था की हुई है कि योजना में सूचीबद्ध दवा हर हाल में मरीज को मिले और वह नहीं हो तो अस्पताल प्रशासन स्थानीय निधि से खरीदकर उपलब्ध करवाए। लेकिन 90 फीसदी मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है। मरीजों को अवैध तरीके से अनुपलब्धता का ठप्पा लगाकर लौटाया जा रहा है।

ठप होने के कारण

दवाओं की आपूर्ति करने वाले राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससी) की उपेक्षा भाजपा सरकार बनते ही शुरू।

आरएमएससी के प्रबंध निदेशक के पद को अस्थायी कर दिया, 7 महीने बाद भी यह पद अतिरिक्त चार्ज के रूप में ही देखा जा रहा है।

आरएमएससी की सतत् गतिविधियां ठप

दवा योजना में कोई नई गतिविधि नहीं

योजना पर एक नजर

शुरुआत	अब तक फायदा	सालाना बजट
2 अक्टूबर 2011 को	20 करोड़ लोगों को	300 करोड़ रुपए होता है

अब तक खर्च बजट	1000 करोड़	एसएमएस की ओपीडी	पहले 8-10 लाख, अब 30 लाख सालाना

निःशुल्क
दवा वितरण
महिलाएं

ये है मंत्री के आदेशों की हालत

चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र राठौड़ पिछले कुछ महीनों से लगातार सभी अस्पतालों से दवाओं की मांग भेजने के निर्देश दे रहे हैं। अधिकांश अस्पतालों से मांग भिजवाई भी जा रही है, लेकिन चिकित्सा मंत्री के आदेशों के बावजूद दवाइयों की आपूर्ति नहीं मिल रही।